भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

11 मई 2011

बिहार में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए माओवादी नेताओं को बिना शर्त रिहा करो!
भाकपा (माओवादी) के केन्द्रीय नेताओं की गिरफ्तारी,
देश के शासक गिरोह द्वारा जनता के ऊपर जारी अन्यायपूर्ण युद्ध
तथा उसके अंतर्गत ही उत्तरप्रदेश के किसानों पर जारी दमन के खिलाफ
21-22 मई को 'भारत बंद' सफल बनाओ!

29 अप्रैल को बिहार के कटिहार जिले के ग्राम बारसोई में केन्द्रीय तथा आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की खुफिया संस्थाओं ने सुनियोजित हमला कर हमारी पार्टी के तीन केन्द्रीय कमेटी सदस्यों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कॉमरेडों में केन्द्रीय कमेटी के सदस्य पुलेंदु शेखर मुखर्जी उर्फ साहेब दा, वारणासी सुब्रह्मण्यम् उर्फ विमल उर्फ श्रीकांत, विजय कुमार आर्य उर्फ जसपाल जी के अलावा बिहार-झारखण्ड स्पेशल एरिया के अंतर्गत उत्तर बिहार-उत्तरप्रदेश रीजनल ब्यूरो सचिव अभिमन्यु उर्फ उमेश यादव, नोखेलाल चौधरी, श्यामजी ऋषि, और आश्रयदाता अनिरुद्ध रविदास शामिल हैं। क्रांतिकारियों की ढूंढ़-ढूंढकर हत्या करने के लिए कुख्यात आंध्रप्रदेश एसआईबी पिछले कुछ महीनों से कॉमरेड सुब्रह्मण्यम् का पीछा कर रही थी। पिछले साल जुलाई के आखिर में वे उसके हमले से बाल-बाल बच गए थे। जब ये कॉमरेड एक बैठक के सिलसिले में इकट्ठे हुए थे, उसी मौके पर केन्द्र-राज्य खुफिया संस्थाओं द्वारा दी गई पक्की सूचना के आधार पर बिहार के एसटीएफ अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया।

पार्टी में साहेब दा, गगन दा, आकाश दा आदि नामों से बुलाए जाने वाले 67 वर्षीय वरिष्ठ माओवादी नेता कॉमरेड पुलेंदु शेखर मुखर्जी पिछले 45 सालों से क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कलकत्ता शहर में पैदा होने वाले साहेब दा नक्सलबाड़ी आंदोलन की प्रेरणा से उच्च शिक्षा को छोड़कर क्रांतिकारी संघर्ष में कूद पड़े थे और जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने लम्बे क्रांतिकारी सफर में उन्होंने बंगाल समेत देश के विभिन्न इलाकों में क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के लिए तथा सच्चे क्रांतिकारियों व कम्युनिस्ट संगठनों की एकता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। दमा, पेट का अल्सर आदि बीमारियों से बुरी तरह पीड़ित होकर भी वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहे।

विमल नाम से आंध्रप्रदेश के क्रांतिकारी खेमे में तथा श्रीकांत के नाम से देश भर में पार्टी कतारों में मशहूर कॉमरेड वारणासी सुब्रह्मण्यम् ने विशाखापटनम के आंध्र विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पूरी करके क्रांतिकारी गतिविधियों में कदम रखा था। 1970 के दशक में उन्होंने रैडिकल छात्र संगठन और बाद में रैडिकल युवा संगठन व सिंगरेणी मजदूर संघ का नेतृत्व किया था। पार्टी के आह्वान पर उत्तर भारत में जाकर उन्होंने वहां के कई राज्यों में क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के लिए अथक प्रयास किए। अपनी गंभीर अस्वस्थता की परवाह किए बगैर वे विभिन्न स्तरों और विभिन्न मोर्चों पर उल्लेखनीय कार्य करते रहे।

विजय कुमार आर्य के नाम से बिहार की जनता में लोकप्रिय कॉमरेड जसपाल जी एक महत्वपूर्ण कॉमरेड हैं जिन्होंने किसानों और सांस्कृतिक मोर्चे का नेतृत्व करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में उल्लेखनीय कार्य किया। पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से वे विभिन्न मोर्चों और विभिन्न इलाकों में क्रांतिकारी क्रियाकलापों का नेतृत्व करते रहे और जन आंदोलनों का निर्माण करते रहे।

बेअंत क्रूरता के लिए बदनाम सीआईए, मोस्साद जैसे विदेशी खुफिया संगठनों द्वारा प्रशिक्षित भारतीय खुफिया अधिकारी क्रांतिकारी आंदोलन का लम्बे समय से नेतृत्व करने वाले कॉमरेडों का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ रहे हैं। दरअसल अमेरिका की सीआईए और एफबीआई ही हमारे देश की खुफिया संस्थाओं को चला रही हैं। पिछले दो सालों में पकड़े जाने वाले अग्रणी कॉमरेडों में पटेल सुधाकर, शाखामूरी अप्पाराव और आजाद की खुफिया संस्थाओं ने हत्या कर दी। कुछ और केन्द्रीय व राज्य स्तर के नेतृत्वकारी कॉमरेडों को गिरफ्तार कर जेलों में कैद किया। इन्हें अलग-अलग राज्यों के झूठे मामलों में फंसाकर लम्बे समय तक बिना किसी जमानत के जेलों में पड़े रहने पर मजबूर किया जा रहा है। झूठी गवाहियां दिलवाकर कठोर सजाएं और आजीवन सजाएं दी जा रही हैं। विभिन्न राज्यों के जेलों में बंद महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को और ज्यादा अमानवीयता के साथ शारीरक और मानसिक यातनाओं का शिकार बनाया जा रहा है। जेलों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित सुशील रॉय, शीला दीदी, नारायण सान्याल, कोबाड गांधी, अमिताभ बाग्ची आदि कॉमरेडों को चिकित्सा सुविधाओं से वंचित कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

तीखे संकट से ग्रस्त विश्व अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए साम्राज्यवादी पिछड़े देशों में संसाधनों की लूटखसोट में तेजी ला रहे हैं। जिन-जिन देशों से वे अपने हितों को जरा भी खतरा महसूस करते हैं उनके खिलाफ वे धौंस व धमकियों पर उतारू हो रहे हैं। जो उनकी बात नहीं मानते उन पर एकतरफा बमबारी करते हुए अन्यायपूर्ण युद्ध कर रहे हैं। भारत के सामंती व दलाल पूंजीपति शासक वर्ग यह झूठा दावा करते हुए कि देश में इस संकट का कोई प्रभाव नहीं है, दिन-ब-दिन संकट में गहरे फंसते जा रहे हैं। साम्राज्यवादी लूटखसोट के लिए सारे दरवाजे खोलते हुए नव उदार नीतियों पर निर्लज्जता से अमल कर रहे हैं। केन्द्र व राज्यों की सरकारें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ लाखों करोड़ों रुपए के एमओयू कर देश की प्राकृतिक सम्पदाओं को औने-पौने दामों में बेच रही हैं। एसईजेड, परमाणु रिएक्टरों की स्थापना, थर्मल बिजली परियोजनाएं, भारी बांध, एक्सप्रेस हाईवे, अभयारण्य आदि योजनाओं के नाम पर जनता से जमीनें बलपूर्वक छीन रही हैं। जल-जंगल-जमीन का, कुल मिलाकर पर्यावरण का विनाश करते हुए जनता को, खासकर आदिवासियों को बेघरबार कर रही हैं। इन नीतियों की आड़ में ही मंत्री, मुख्यमंत्री और नौकरशाह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व घोटाले करते हुए लाखों करोड़ रुपए डकार रहे हैं। इस तरह जमा किए गए काले धन को स्विस बैंकों में छुपा रहे हैं। इस तरह वे मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों और मध्यम वर्ग की जिंदगी दूभर बना रहे हैं। जहां एक ओर टाटा, बिड़ला, अंबानी, जिंदल, मित्तल, महेंद्रा, रुइया, निको जयस्वाल, सन नेटवर्क आदि अपनी सम्पत्तियों को हजारों, लाखों करोड़ों में बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की 77 फीसदी जनता रोजाना 20 रुपए से भी कम आमदनी से भूखों मर रही है। भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, विस्थापन, बीमारियां, कुपोषण आदि समस्याओं के भंवर में फंसकर देश की जनता छटपटा रही है। इसका विरोध करने वाली और आंदोलन करने वाली जनता का लौह पैरों से रौंदने के लिए शासक लाखों पुलिस व अर्धसैनिक बलों का प्रयोग कर रहे हैं। नागरिक व जनवादी अधिकारों का हनन करते हुए काले कानून बना रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए का जन धन पानी की तरह बहा रहे हैं ताकि जनता का दमन करने वाली मशीनरी के पंजों की धार बढ़ाई जा सके।

लुटेरे शासक वर्गों के प्रति जनता में फूट पड़ रहे असंतोष और आक्रोश से माओवादी आंदोलन को मजबूती मिल रही है, इस सचाई को चिन्हित कर शासक वर्गों ने सुनियोजित तरीके से यह प्रचार शुरू किया कि 'माओवादी आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है'। माओवादी आंदोलन को हिंसावाद के रूप में तथा माओवादी पार्टी को आतंकवादी संगठन के रूप में चित्रित करते हुए बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार मुहिम शुरू कर दी। अपनी साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों को लागू करने तथा उसके अंतर्गत संसाधनों की लूटखसोट के रास्ते में माओवादी पार्टी को बहुत बड़ी बाधा मानते हुए उन्होंने माओवादी पार्टी का जड़ से सफाया करने के लक्ष्य से खासकर पिछले दो सालों से एक बेहद पाशविक व फासीवादी हमला शुरू किया जिसका नाम 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' रखा गया है। माओवादी आंदोलन के इलाकों में विभिन्न स्तरों पर विकसित हो रही वैकल्पिक जन राज्यव्यवस्था का भी गला घोंटने के लक्ष्य से जारी इस हमले में जनवरी 2011 से तेजी लाई गई और इसे अब 'ऑपरेशन ग्रीन हंट-2' कहा जा रहा है। इसके तहत पुलिस, अर्धसैनिक व विशेष बलों तथा उनके द्वारा बनाए गए प्रति-क्रांतिकारी गुण्डा गिराहों ने आंदोलन के क्षेत्रों में फर्जी मुठभेड़, कत्लेआम, गांव-दहन, लूट, महिलाओं पर बलात्कार, गिरफ्तारी और बर्बर यातना का सिलसिला तेज कर दिया। शासक वर्ग छत्तीसगढ़ में सेना की तैनाती की तैयारियां पूरी करके माड़ क्षेत्र में 800 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। माड़ क्षेत्र और छत्तीसगढ़-ओड़िशा की सीमा पर दो सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने जा रहे हैं। वायु सेना के बेस स्थापित करने की तैयारियों के अलावा 'आत्मरक्षा' के नाम पर उसे हमले करने का अधिकार भी दे दिया गया है।

दण्डकारण्य (छत्तीसगढ़) के चिंतलनार इलाके में 11 से 16 मार्च तक 350 कोबरा बलों, कोया कमाण्डों बलों और सैकड़ों एसटीएफ बलों ने मोरपल्ली, तिम्मापुरम और ताड़िमेटला गांवों पर भारी तबाही मचाकर 300 घरों में आग लगा दी। हजारों कुंटल अनाज जला दिया। घर-घर को लूटा। तीन ग्रामीणों की हत्या की। दो ग्रामीणों को लापता कर दिया। पांच महिलाओं के साथ बलात्कार किया। करीब 50 ग्रामीणों के साथ बुरी तरह मारपीट की। इसकी जांच-पड़ताल के लिए जा रहे जनवादियों, रिपोर्टिंग के लिए जा रहे मीडियाकर्मियों तथा पीड़ितों को राहत-सामग्री ले जा रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फासीवादी मुख्यमंत्री रमनसिंह, शासक वर्गों के वफादार कुत्ते डीजीपी विश्वरंजन, बस्तर आईजी लांगकुमेर और दंतेवाड़ा एसएसपी कल्लूरी ने सोची-समझी साजिश के तहत सलवा जुडूमी गुण्डों से हमले करवाकर उन्हें उस इलाके में जाने से रोक दिया। इन घटनाओं को लेकर प्रदेश और देश में बड़े पैमाने पर हुए प्रचार की पृष्ठभूमि में रमनसिंह को ताड़िमेटला गांव के दौरा करने पर मजबूर होना पड़ा। उस मौके पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की सभा चल ही रही थी, तो दूसरी तरफ कोया कमाण्डो दरिंदों ने गांव के दूसरे कोने में फिर 15 घरों में लूटपाट मचाई और कुछ लोगों के साथ मारपीट कर एक महिला के साथ बलात्कार किया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में फासीवादी आतंक कितना भयावह रूप धारण कर चुका है। इस तरह के हमले बस्तर क्षेत्र के साथ-साथ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आए दिन किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन इलाकों में गोपनीय हत्यारे दस्तों को उकसाकर जन संगठन कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाई जा रही हैं। खासतौर पर महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार और हमले करवाए जा रहे हैं। 19 अप्रैल को नारायणपुर जिले के चिनारी गांव में 14 वर्षीय किशोर रजनू की हत्या कर मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी गई। दण्डकारण्य में आए दिन चल रहे भीषण दमनचक्र के ये चंद ताजा उदाहरण भर हैं।

14 मार्च को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने तीन महिलाओं समेत छह माओवादी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या की। कुछ अन्य कॉमरेडों को गिरफ्तार किया। झारखण्ड सरकार माओवादी नेताओं की हत्या करने के बुरे मंसूबे से हजारों पुलिस व अर्धसैनिक बलों को उतारकर हमले कर रही है। अंधाधुंध गिरफ्तारियां चला रही है। विस्थापन और जबरिया जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर फासीवादी हमले कर रही है। ओड़िशा में दलाल नवीन पटनायक सरकार ने राज्य के चारों कोनों में फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला चलाकर पिछले चार महीनों में ही 25 से ज्यादा माओवादी कार्यकर्ताओं, खदान-विरोधी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की हत्या की। मृतकों में 12 वर्षीय बालिका जांगा और कुछ अन्य किशोरियां भी शामिल हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पटनायक सरकार की दमनकारी नीतियों ने कितना घिनौना रूप ले लिया है।

पिछले 34 सालों से जारी अपने फासीवादी शासन को किसी भी तरह टिकाए रखने के लक्ष्य से पश्चिम बंगाल की सीपीएम सरकार ने चुनावों के पहले जनता और माओवादियों पर हमले तेज किए। पुलिस व अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ अपनी गुण्डा वाहिनी - हर्मद बाहिनी के जरिए वह अमानवीय हत्याकाण्डों और जघन्य अपराधों को अंजाम दे रही है। नेताई हत्याकाण्ड, शशधर महतो की हत्या जैसी घटनाएं चंद ताजा उदाहरण हैं। गिरफ्तार माओवादी नेताओं पर, खासकर महिलाओं पर वह अमानवीय हिंसा कर रही है। हाल ही में मेदिनीपुर जेल में हड़ताल कर रहे राजनीतिक कैदियों पर उसने पुलिस बलों को उकसाकर हमला करवाया। राज्य में माओवादी आंदोलन का सफाया करने का ढिंढ़ोरा पीटने वाली आंध्रप्रदेश सरकार ने अपने पुलिस बलों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी रखा हुआ है। माओवादी नेताओं को पीछा कर मार डालने की नीतियों में उसने तेजी लाई। पृथक तेलंगाणा राज्य के लिए आंदोलनरत जनता का वह दमन कर रही है। महाराष्ट्र सरकार आदिवासी आंदोलन के क्षेत्रों में सी-60 कमाण्डों बलों के सहारे दमनचक्र को लगातार तेज कर रही है। शहरी इलाकों में माओवादी नेताओं और जनवादियों को गिरफ्तार कर उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसा रही है।

यह फासीवादी हमला सिर्फ माओवादी आंदोलन पर ही नहीं चल रहा है। लुटेरे शासक वर्ग हर जनवादी आंदोलन पर फासीवादी दमन का ही प्रयोग कर रहे हैं। पिछले माह 18 तारीख को महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु बिजली परियोजना के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर पुलिस ने गोली चलाकर तबरेज़ नामक एक प्रदर्शनकारी की जान ली। और अब उत्तरप्रदेश में ग्रेटर नोइडा से आग्रा तक प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए अपनी जमीनें देने से इनकार करने वाले किसानों पर पुलिस बल पाशविक दमनचक्र चला रहे हैं। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। कम से कम दो किसान मारे गए। पुलिसिया जुल्म का भट्टा-परसौल और उसके आसपास के गांवों की जनता ने बहादुराना तरीके से प्रतिरोध किया। इसमें दो पुलिस वाले मारे गए, जबकि कुछ अन्य अधिकारी व पुलिस वाले घायल हो गए। अगले दिन आग्रा, अलीगढ़ आदि इलाकों में भी जनता ने अपना आंदोलन तेज

कर दिया। पुलिस जुल्म का प्रतिरोध किया। इस बहाने फासीवादी मायावती सरकार उत्तरप्रदेश के किसानों पर तीव्र दमन चला रही है। गांवों की नाकेबंदी कर जनता के ऊपर कई अत्याचार कर रही है।

प्यारे लोगो! जनवाद के प्रेमियो! देशभक्तो! उपरोक्त फासीवादी दमनात्मक कार्रवाइयां और माओवादी नेताओं की गिरफ्तारियां ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से जारी उस युद्ध का हिस्सा हैं जिसे देश का शासक गिरोह - यानी सोनिया-मनमोहनसिंह-चिदम्बरम गिरोह साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ से देश की जनता के खिलाफ चला रहा है। विश्व पूंजीवादी व्यवस्था जिस तीव्र संकट में फंसी हुई है, उसका प्रभाव हमारे देश के सभी क्षेत्रों में पड़ रहा है और इसी पृष्ठभूमि में इस राजनीतिक दमन, हत्याकाण्डों और मानवाधिकारों पर हमलों को समझना चाहिए। माओवादी आंदोलन का जड़ से सफाया कर लुटेरी सरकारों की साम्राज्यवाद-परस्त और जन-विरोधी नीतियों को बेरोकटोक जारी रखने की साजिश का ही हिस्सा है यह सब। यह एक ऐतिहासिक सचाई है कि दमन प्रतिरोध को जन्म देता है। सोनिया-मनमोहनसिंह-चिदम्बरम शोषक शासक गिरोह हत्याओं, गिरफ्तारियों और दमनात्मक मुहिमों से जन आंदोलनों और क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने का जो सपना देख रहा है वह दिवास्वप्न ही साबित होगा। कॉर्पोरेट घरानों को अंधाधुंध मुनाफा पहुंचाकर किसानों व आदिवासियों को बेघरबार करने वाला 'विकास' का ढोंगी नमूना देशवासियों पर थोपते हुए, देश को बेचने वाले ये सामंती, दलाल पूंजीपति शासक वर्ग और उनको चलाने वाले साम्राज्यवादी ही बहुत बड़े दुश्मन हैं जिनसे हमारे देश के विकास, स्वावलम्बन, सम्प्रभुता, स्वतंत्रता और जन कल्याण को भारी खतरा है। हमारी केन्द्रीय कमेटी का यह आह्वान है कि इन दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य से हमारी पार्टी की अगुवाई में जारी जनयुद्ध तथा नई जनवादी क्रांति में आप सब बड़े पैमाने पर गोलबंद हों। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, जनवादियों और शांति वार्ता की हिमायत करने वालों से हमारी केन्द्रीय कमेटी अपील करती है कि वे हमारे आंदोलन के इलाकों का दौरा कर यहां पर हो रहे अमानवीय दमन और हत्याकाण्डों की खुद जांच-पड़ताल करें। हमारी केन्द्रीय कमेटी यह आग्रह करती है कि 'दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र' कहलाने वाले इस देश के बीचोबीच बेहद गरीब जनता पर, आदिवासियों पर हो रही सरकार की फासीवादी हिंसा से जुड़ी सचाइयां देश की तमाम जनता के सामने उजागर करें।

हमारी केन्द्रीय कमेटी जनता और जनवादियों का यह आह्वान करती है कि वे इन गिरफ्तारियों, कत्लेआमों, पुलिसिया जुल्म, तबाही, लूटपाट, अत्याचारों, दुष्प्रचार, राज्य के फासीकरण, जबरिया जमीन अधिग्रहण और यूएपीए जैसे काले कानूनों का खण्डन करें और इसके खिलाफ एकजुटता से संघर्ष करें। सरकार से हमारी मांग है कि माओवादी नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए। सरकारी फासीवादी आतंक का एकजुटता और जुझारू तरीके से प्रतिरोध करना ही एक मात्र रास्ता है, अत: हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम क्रांतिकारी जनता का यह आह्वान करती है कि वह इसके लिए हिम्मत के साथ आगे आए। हम स्पष्ट करते हैं कि पार्टी और पीएलजीए के नेतृत्व में जारी जन प्रतिरोधी आंदोलन को और ज्यादा तेज कर तथा इसमें हजारों, लाखों की संख्या में गोलबंदी से ही इस हमले को पराजित किया जा सकता है।

हमारी केन्द्रीय कमेटी देश की तमाम जनता से अपील करती है कि माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी, जनता के ऊपर देश के शासक गिरोह द्वारा जारी युद्ध और उत्तरप्रदेश के किसानों पर जारी दमन के खिलाफ 21-22 मई को 48-घण्टों का 'भारत बंद' सफल बनाया जाए। यह बंद प्रमुख रूप से 6 राज्यों - झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के तीन जिलों - गढ़चिरौली, चंद्रपुर और गोंदिया में, मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में तथा उत्तरप्रदेश के बिहार के सीमावर्ती जिलों में लागू किया जाएगा। अन्य राज्यों में विभिन्न रूपों में विरोध कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हालांकि हम चिकित्सा सेवाओं, छात्रों की परीक्षाओं व साक्षात्कार जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखेंगे।

Abhay

(अभय)
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)